PACS

Bihar Development Conference

21-22 August 05
Patna

PACS

Bihar Development Conference

21-22 August 05
Patna

Hindustan Times

Monday, August 22, 2005
Hindustan Times, Patna

Give fair deal to fair sex: Experts

HT Correspondent
Patna, August 21

UNLESS DALITS, tribals, deprived sections and women are given tools or instruments of change, any amount of empowerment will fail to deliver, according to experts addressing the two-day Bihar Development Conference (BDC) on Poorest Area Civil Society (PACS), which began here on Sunday.

The PACS programme is aimed at evoking statewide attention towards the growing nature of poverty, deprivation and helplessness of the poor. The programme seeks to achieve this goal through capacity building of Civil Society Organisations (CSOs) to assist people living in the poorest districts demand rights and entitlements more effectively.

Formally inaugurating the BDC, chief guest Malini Bhattacharya, member, National Commission for Women and former MP, referring to women, said that despite all round gloom and despair there were some positive signs. She singled out reservation for women in Panchayats as a step towards a new direction, while also underlining the need for legal protection to women, including Pre-Natal Diagnostic Technique Act, Anti-Dowry Act, etc.

Similarly, self-help groups provided economic freedom to women, opening new avenues for them, Bhattacharya noted. However, she could not help terming this kind of 'empowerment' of women as mere shout in the wilderness. She, however, said such shouts would have to become shriller to be more effective.

HT
Former MP Malini Bhattacharya inaugurating the conference on PACS in Patna on Sunday.

She demanded restoration of women's role in traditional system of agriculture. She expressed concern over denial of tribals' traditional rights over forests and non-recognition of domestic labour put in by housewives and working women alike.

Speaking as the guest of honour, former Patna High Court judge Prem Shankar Sahay, regretted that even after 58 years of independence there was no perceptible change in rural Bihar, despite allocation of crores of rupees by the Centre towards a plethora of poverty alleviation programmes. He wondered where all the money went and remarked, "This is shameful." He complimented the NGOs for doing real and dedicated work for empowerment of the poor.

Sahay lamented that political parties had never paid any attention to education fearing that educated masses would unseat them from power. Dr A K Basu, chairman, PSC, PACS and a former member of steering committee of the Planning Commission, said that women's development and empowerment was a prerequisite for any change in Bihar. Women would have to be given tools of change, he asserted, complaining, "unfortunately, the JP movement had paid no attention to women."

News Reports from Patna, 22nd August 2005

PACS

Bihar Development Conference

21-22 August 05

Patna

पटना, रांची, दिल्ली और लखनऊ से प्रकाशित

हिन्दुस्तान

www.hindustandainik.com

पटना, सोमवार, 22 अगस्त, 2005

महिलाओं को सशक्त बनाकर ही बन सकता है सबल समाज

राज्यस्तरीय विकास कांफ्रेंस शुरू

पटना (हि.प्र.)। गरीबी के साथ ही जुड़ी है महिलाओं की समस्या। गरीबी उन्मूलन के साथ-साथ महिला सशक्तीकरण संभव है। गरीबी भुखमरी बेरोजगारी से जूझ रहे बिहार में स्वयं सहायता समूह और अन्य माध्यमों से महिलाओं को सबल बनाकर समाज को सबल बनाया जा सकता है। ये बातें पुअरेस्ट एरिया सिविल सोसाइटी (पेक्स) पर स्थानीय मौर्य होटल में आयोजित दो दिवसीय कांफ्रेंस में वक्ताओं ने कही। कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य मालिनी भट्टाचार्य ने कहा कि महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में स्वयं सहायता समूह एक बेहतर कदम है। बिहार में पेक्स के राज्य प्रबंधक राकेश झा ने कहा कि बिहार के 21 जिलों में यह कार्यक्रम चलाया यजाना है। इसे तीन कलस्टर में बांटा गया है। उत्तर बिहार, दक्षिण बिहार और पठारी क्षेत्र। भूमि का अधिकार और कार्यकर्ताओं में क्षमता विकसित किया जाना इसकी मुख्य चुनौतियां है। देश भर के सबसे गरीब जिलों में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। पंचायती राज में चुनी हुई महिलाएं सामुदायिक कार्यक्र मों को चलाने के लिए उपयुक्त है। बिहार में पेक्स से साढ़े चार लाख लोग सीधे जुड़े हैं। भविष्य में इस कार्यक्रम से आठ लाख लोगों को जोड़ने की योजना है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष मंजु प्रकाश ने गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में महिलाओं को जोड़ने की बात कही। कार्यक्रम में बिहार की झुग्गी झोपड़ियों की समस्या और महिलाओं को सशक्तीकरण पर आधारित अमिताभ पांडेय की एक डाक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई गई। कार्यक्रम को डा. ए.के बसु, प्राथमिक और वयस्क शिक्षा सचिव डा. विजय प्रकाश , किरण शर्मा आदि ने भी संबोधित किया।

राष्ट्रीय आय में शामिल होगी घरेलू कार्य की कीमत

पटना (हि.प्र.) । राष्ट्रीय आय में शामिल होगा महिलाओं का घरेलू कार्य। यह प्रस्ताव राष्ट्रीय महिला आयोग सरकार के समक्ष रखने वाली है। आयोग की प्रतिनिधि और दो बार पं. बंगाल के जाधवपुर लोक सभा सीट से सांसद रह चुकी मालिनी भट्टाचार्य ने कहा कि घरेलू श्रम को अगर राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाए तभी महिलाओं की सामाजिक हैसियत बढ़ सकती है। वह देश के भविष्य के लिए खाना बनाती है। वे सामाजिक श्रम कर रही हैं, इसकी कीमत का निर्धारण तो होना ही चाहिए। परिवार की जिम्मेदारी निभाती बगैर किसी वेतन के। यदि महिलाओं के घरेलू काम का मूल्य निर्धारण होगा तभी समाज उनके काम की महत्ता समझ सकेगा। महिलाओं को तब बोझ नहीं समझा जाएगा। साथ ही उन्होंने यह जोड़ा की घर का काम और बाहर को काम दोनों करने वाली महिलाओं के लिए सरकार को कम कीमत पर कैंटिन में भोजन की सुविधा और बच्चों को रखने के लिए क्रैश की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। वे घर का काम करके सामाजिक दायित्व की पूर्ति के साथ आर्थिक ईकाई भी बन रही हैं, इसका लाभ उन्हें मिलना ही चाहिए। बिहार की महिलाओं की समस्या को लेकर उन्होंने कहा कि केवल शिक्षा उनकी स्थिति नहीं सुधार सकता। पिछले वर्षों में दूसरे जगह जाकर वे काम तलाश रही हैं। राज्य से महिलाओं के प्रवजन को रोकना होगा। बिहार के कुछ जिले ट्रैफि किंग से भी प्रभावित हैं। सबसे पहले महिलाओं को गरीबी से निकालना होगा। उन्होंने बताया कि वे राज्य महिला आयोग गई थी। उनके साथ मिलकर वे महिलाओं की समस्या सुलझाएंगी। वे राज्य आयोग के संपर्क में रहेंगी। फिलहाल जन अदालत लगाकर या फिर साथ सेमिनार करकेबिहार की महिलाओं की समस्या का समाधान ढूढा जाएगा। इस संदर्भ में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष मंजू प्रकाश ने कहा कि राष्ट्रीय आयोग के साथ मिलकर महिलाओं की समस्या का समाधान ढूढने की दिशा में यह पहल अच्छी है। एपवा प्रतिनिधियों ने अररिया बरवा कांड में सामंतों द्वारा चंपारण की महिलाओं की हत्या और बलात्कार की घटना को लेकर सुश्री भट्टाचार्य को एक ज्ञापन दिया गया जिसमें कहा गया है कि आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई।

News Reports from Patna, 22nd August 2005

PACS

Bihar Development Conference

21-22 August 05
Patna

दैनिक जागरण

पटना, 22 अगस्त, 2005

'जातिवाद सूबे के विकास में सबसे बड़ी बाधा'

पटना, हमारे प्रतिनिधि : राजधानी में रविवार को स्थानीय एक होटल में आयोजित 'बिहार विकास सम्मेलन' में आये आये वक्ताओं ने कहा कि राज्य के विकास में जातिवाद सबसे बड़ा रोड़ा बन गया है। महिलाओं के विकास से ही सूबे के विकास की मार्ग खुल सकता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्राथमिक शिक्षा सचिव विजय प्रकाश ने कहा कि शिक्षा ही वह माध्यम है, जिससे राज्य के युवा काम में कुशलता और दक्षता हासिल कर सकते हैं। मौके पर नयी दिल्ली स्थित इण्डियन सोशल इंस्टीच्यूट के पूर्व निदेशक डा.प्रकाश लुईस ने रच्च्य के पिछड़ेपन के कारणों को रेखांकित करते हुए कहा कि वर्तमान में राज्य जातिवाद के कुचक्र में फंस गया है। इस अवसर पर बिहार महिला आयोग की अध्यक्ष मंजू प्रकाश ने कहा कि महिलाओं को दोयम दर्जे की नागरिकता देकर सूबे के विकास की कल्पना करना बेकार है।

News Reports from Patna, 22nd August 2005

PACS

Bihar Development Conference

21-22 August 05

Patna

प्रभात खबर

पटना, मंगलवार, 23 अगस्त, 2005

विकास के लिए एकजुट हो कर काम करना होगा : शर्मा

पटना, 22 अगस्त : भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सुभाष शर्मा ने कहा कि देश के चौतरफा विकास के लिए आर्थिक विकास के साथ ही सामाजिक विकास भी जरूरी है. उन्होंने कहा कि इसके लिए जरूरी है कि सरकार व स्वयंसेवी संस्थाएं एक साथ मिल कर विकास की दिशा में काम करें .वे आज यहां पैक्स के दो दिवसीय सम्मेलन के समापन के अवसर पर ,प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि किसी भी काम को शुरू करते समय उसकी स्थानीय जरूरतों का ख्याल रखना जरूरी है. नवार्ड के मुख्य महाप्रबंधक बीएस भंडारी ने कहा कि हमलोगों के द्वारा जिन समुहों को सहायता प्रदान की जाती है, उनमें 90 फीसदी से अधिक महिलाएं शामिल हैं. उन्होंने कहा कि स्वयंसेवी संगठनों को चाहिए कि वे सुविधाओं को छोटे स्तर पर फैलाने का काम करें, ताकि समाज की पिछली पंक्ति के लोगों को सीधा लाभ मिल सके. पैक्स के तहत राज्य में कुल 34 योजनाओं पर काम शुरू किया जाना है, जिनमें करीब 84 स्वयंसेवी संस्थाओं की सहभागिता होगी. खासतौर पर इस योजना के तहत महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए उन्हें लघु उद्योगों की ओर प्रेरित और प्रशिक्षत करना होगा. उद्योग शुरू करने के लिए उन्हें ऋण मुहैया कराने में सहायता देनी होगी.

■ पैक्स का दो दिवसीय सम्मेलन

News Reports from Patna, 23rd August 2005

PACS

Bihar Development Conference

21-22 August 05
Patna

दैनिक जागरण

पटना, मंगलवार, 23 अगस्त, 2005

कृषि को बढ़ावा देने से ही विकास

हमारे प्रतिनिधि, पटना

भारत एवं ब्रिटेन के संयुक्त त्वावधान में चलाये जा रहे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सोमवार को राजधानी में आयोजित बिहार विकास सम्मेलन में आये वक्ताओं ने जोर दिया कि कृषि का विकास किये बिना राज्य का विकास संभव नहीं है। इस अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्वी क्षेत्र के निदेशक डा. आलोक कुमार सिक्का ने कहा कि राज्य कि विकास की नींव कृषि है। यहां पर कृषि आधारित उद्योग ही राज्य के विकास के द्वार खोल सकते हैं।

मौके पर राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डा. पी. एन. झा ने कहा कि अब समय आ गया है कि सरकार कृषि को बढ़ावा देने के लिए अविलम्ब अभियान शुरू करें। इस अवसर पर डा. वासु, डा. प्रकाश लुईस, राकेश झा एवं समीर सहित कई लोगों ने भाग लिया।

News Reports from Patna, 23rd August 2005

PACS

Bihar Development Conference

21-22 August 05

Patna

पटना, रांची, दिल्ली और लखनऊ से प्रकाशित

हिन्दुस्तान

नगर

www.hindustandainik.com

पटना, मंगलवार, 23 अगस्त, 2005

बिहार डेवलपमेंट कांफ्रेंस का समापन

पटना (हि.प्र.)। स्थानीय शासन, आर्थिक सशक्तीकरण, महिला सशक्तीकरण और सुझावों जरिये गरीबतर जिलों में गरीबों को दीर्घकालीन विकास की ओर अग्रसर करना है। गरीबी हटाने के इस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबों को गरीबी के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया जाना है न कि उन्हें सहायता देकर पंगु बनाया जाना। यह संकल्प पेक्स से जुड़े गैर सरकारी संगठनों ने सोमवार को लिया। बिहार विकास कांफ्रेंस के समापन सत्र पर गैर सरकारी संस्थाओं ने विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से गरीबी पर चौतरफा प्रहार के गुर सीखें और उन्हें प्रशासनिक कठिनाइयां भी बताई।

इस मौके पर आयोजकों ने कहा कि पुअरेस्ट एरिया सिविल सोसाइटी प्रोग्राम का उद्देश्य गरीब समुदाय का विकास के दीर्घकालीन कार्यों में लगाना है। देश भर के 170 पिछड़े जिलों में सिविल सोसाइटी ऑरगेनाइजेशन(सीएसओ) के जरिए यह कार्यक्रम चलाया जाना है। कार्यक्रम में 170 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। बिहार के 21 जिलों में 84 गैर सरकारी संगठन इस कार्यक्रम में लगे हैं। बिहार में पेक्स कार्यक्रम के द्वारा महिला सशक्तीकरण, पंचायती राज में उनकी भागीदारी, उनके आर्थिक सशक्तीकरण पर विशेष बल दिया जाएगा। दो दिवसीय कांफ्रेंस के समापन पर नेशनल सेविंग फाइनांस विभाग के सचिव सुभाष शर्मा ने कहा कि विकास का अर्थ केवल आर्थिक विकास नहीं बल्कि सामाजिक विकास भी होना चाहिए। नाबार्ड के सीजीएम बी.एस भंडारी ने कहा कि नाबार्ड की सहायता से अबतक 16, 18000 समूह बनाए जा चुके है। नाबार्ड से सहायता प्राप्त समूहों में 90 फीसदी महिलाएं हैं। काम्फेड के प्रबंध निदेशक गिरीश शंकर ने कहा कि कांफेड के तहत 2.56 लाख लोगों को स्वरोजगार मिला है। दूध की सहकारी समितियां और लोग डेयरी के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। इस कारण कांफेड का टर्न ओवर 450 करोड़ प्रतिवर्ष हो गया है। गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने इस मौके पर कई सवाल अधिकारियों के समक्ष रखे विश्व बैंक के प्रतिनिधि प्रमेश शाह, स्टेट बैंक के अधिकारी गौरी शंकर सिंह पूसा कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति पी.एन.झा, पेक्स की निदेशक किरण शर्मा, इकार के निदेशक, जल संसाधन विभाग के आर.एन लाल, पेक्स के पीडीआरओ राजेश्वर आदि ने भी संबोधित किया।

News Reports from Patna, 23rd August 2005

PACS

PACS Bihar Coordination Office
4A, Ruchira Apartments, A.N Path, North
S.K Puri
Patna - 800013